<u>प्रसार भारती</u>

<u>भारतीय प्रसारण निगम</u>

<u>आकाशवाणी केन्द्र शिमला</u>

<u>23.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे</u>

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी सरकार के विचाराधीन है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक लोकेन्द्र कुमार के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कार्यालय के स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। विधायक सुधीर शर्मा के एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हिमकार्ड में रियायत देने पर सरकार विचार कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 2 लाख हिम कार्ड बनाए जा चुके हैं और हिम कार्ड बनाने की डेट एक्सटेंड करने का फैसला निगम की बीओडी की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है इसलिए उनका कार्ड बनाना भी जरूरी है। विधायक मलेन्द्र राजन के एक सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों व खड्डों की चैनलाईज़ेशन पर जब तक केन्द्र की प्राथमिकता नहीं बदलती है, तब तक इन्हें आगे बढ़ाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी, चक्की खड्ड व अन्य खड्डों में बाढ़ से बचाव के लिए तटीकरण व सुरक्षा परियोजना बनाने का मामला विचाराधीन है।

वॉकआउट

प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष के विरोध के बावजूद मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2005 संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार पैट्रोल–डीज़ल पर 5 रूपए तक विधवा व अनाथ सैस लगाएगी। इस दौरान विपक्ष ने बिल का विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि पैट्रोल–डीज़ल के दाम बढ़ने से प्रदेश के सभी वाहन चालकों पर असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी वहीं राज्य सरकार को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा की तुलना में पैट्रोल–डीज़ल अभी सस्ता है लेकिन अतिरिक्त सैस लगने से ये महंगा हो जाएगा।

<u>मंत्रिमण्डल</u>

प्रदेश में अब चिट्टे में संलिप्त व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने फैसला लिया कि जिनके खिलाफ भी चिट्टे के मामले दर्ज हैं या चिट्टे से संबंधित मामले की चार्जशीट कोर्ट में फाईल हो चुकी है, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में मंत्रिमण्डल ने अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमण्डल ने टांडा मैडिकल कॉलेज के लिए पैट स्कैन मशीन खरीद को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा आई.जी.एम.सी., शिमला हमीरपुर और नेरचौक मैडिकल कॉलेज में बायोफिजिक्स विभाग खोलने की स्वीकृति दी गई। बैठक में मैडिकल कॉलेजों में इंटर

कॉलेज बनाने को भी स्वीकृति दी गई। सरकार ने गैस की कमी को दूर करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मज़बूत करने को मंजूरी दी ताकि भविष्य में रसोई गैस की किल्लत न हो।

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने केन्द्र सरकार से सिरमौर ज़िले में पच्छाद विधानसभा से जुड़े सराहां–चंडीगढ़ मार्ग के सुधार, चौड़ीकरण और स्थायी सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। लोकसभा में नियम 3 सौ 77 के तहत ये मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये न केवल क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, बल्कि प्रदेश को हरियाणा व चण्डीगढ़ से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग भी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस मार्ग की खराब हालत के चलते लोगों को आवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है जिससे ये मार्ग जोखिमपूर्ण हो गया है।

डीसी शिमला

शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया है कि भारत नेट परियोजना के माध्यम से ज़िले की 19 पंचायतों को जोड़ दिया गया है। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि शेष ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य जारी है। उपायुक्त ने कहा कि ज़िले के दूरदराज़ क्षेत्र डोडरा क्वार की ग्राम पंचायतों को भी भारत नेट परियोजना के साथ जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की भारत नेट परियोजना का उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबेंड नेटवर्क का निर्माण करना है।

....